1	2	3	4
Jammu & Kashmir	4,56,000	4,50,000	4,50,000
Karnataka	2,97,937	1,51,630	1,14,645
Kerala	1,21,385	87,189	58,443
Madhya Pradesh	3,02,571	2,05,306	1,36,635
Maharashtra	6,87,673	5,82,923	5,68,052
Nanipur	1,029	424	424
Orissa	1,64,714	1,44,588	1,31,598
Punjab	1,39,225	1,01,332	99,301
Rajasthan	5,90,428	5,49,228	3,91,031
Tamil Nadu	1,62,981	1,53,616	1,34,398
Tripura	2,011	1,911	1,502
Uttar Pradesh	5,03,215	4,76,358	4,44,252
West Bengal	11,85,631	10,88,293	8,06,739
Dadra, Nagar & Haveli	8,958	6,776	4,095
Delhi	1,145	1,103	284
Pondicherry	2,300	1,141	899
TOTAL	73,55,919	58,37,104	45,09,466

Legal aid Committees at State Level

1985. SHRIMATI ILA BHATTACHARYA : Will the Minister of WELFARE be pleased to state :

(a) what is the number of Legal Aid Committees that have so been i die State level with a view to *c* legal assistance to the landless Adivasis Statewise; and

(b) the ex' Legal Aid C succe^ ferret and I Pradesh three years?

THE OF W]
(SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) and (b) The requisite information is being collected from the State Governments/Union Territories and will be laid on the Table of the House later.

Pan Masala Advertisement

* 1986. SHRI O.J. JOSEPH : the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING b to state :

Government have any representation from a avion *£or* bannine ment 011 'Pan Masala' on health rounds; and

(b) if so, what are the d thereof and the action by Government, thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL) :(a) and (b) Government have received representations from viewers about injurious effects of Pan Masala on throat. Views of Ministry of Health in the matter were sought and their advice is that there is no evidence that Pan Masala is harmful to human health.

सरकारी कालोनियों में क्वार्टरों को अनधिकृत शिकमी किरायदारी

1987. **श्री रफीक आलम :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सरकारी कालोनियों में क्वार्टरों की अनधिकृत शिकमी किरायेदारी की जानकारी है; यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ;

(ख) क्या एन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली में कोई सर्वेक्षण कराया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एन्ड्रयूजगंज में क्वार्टरों का सर्वेक्षण कराने और उन क्वार्टरों को खाली कराके प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को देने का विचार रखती है जिनमें शिकमी किराएदार रह रहे हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सर्वेक्षण कब तक पूरा करा लिए जाने की संभावना है और इस संबंध में अब तक क्या किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । उप किराएदारी के मामलों का पता लगाने के लिए विभिन्न सरकारी कालोनियों में अचानक जांच करके अचानक सर्वेक्षण किए गए हैं । उप किराएदारी के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है ।

(ख) और (ग) जी, हां । आवंटन नियमों के अन्तर्गत दोषी आवंटियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । उन मामलों जहां उप किराएदारी साबित हो जाती है, क्वार्टर का आवंटन रद्द कर दिया जाता है तथा प्रतीक्षा सूची के अन्य व्यक्तियों को आवंटन के लिए क्वार्टरों को खाली करा लिया जाता है ।

(घ) यह एक सतत प्रक्रिया है ।

Sugar production in Private and Cooperative Sectors

1988. DR. MOHD! EAPKTM KIDWAI : Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state :

(a) what is the number of sugar factories started in cooperative sector in the country, State-wise from 1982 to 1985;

(b) the number of sugar factories started by private managements in the country, State-wise during the above period; and

(c) the comparative production figures of the sectors?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI K.P. SINGH DEO) : (a) and (b) Statement-I giving the position for the years 1981-82 to 1984-85 is attached.

(c) Statement-II indicating the figures of sugar production in Co-operative and private Sector for the years 1981-82 to 1984.-85 is attached.